



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939

No. 654]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

गृह मंत्रालय

(सी. एस. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

**सा.का.नि. 950(अ).—**केन्द्रीय सरकार, कैदियों का संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध बोस्निया एवं हर्जोगोविना पर लागू होंगे। सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और बोस्निया एवं हर्जोगोविना द्वारा दिनांक 13.12.2012 को हस्ताक्षरित करार का सम्पूर्ण पाठ नीचे दिया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.02.2013 को और बोस्निया एवं हर्जोगोविना द्वारा दिनांक 10.12.2015 को इस करार का अनुसमर्थन किया गया। अनुसमर्थन की लिखत का आदान-प्रदान दिनांक 21.07.2017 को किया गया।

**भारत गणराज्य और बोस्निया एवं हर्जोगोविना के बीच सजायाफ्ता कैदियों के अंतरण संबंधी करार**

भारत गणराज्य और बोस्निया एवं हर्जोगोविना जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संविदाकारी राष्ट्र कहा गया है;

सजायाफ्ता कैदियों के लिए अपने-अपने देशों में सामाजिक पुनर्वास सुविधाजनक बनाने की इच्छा रखते हुए; और

यह विचार करते हुए कि यह उद्देश्य अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध हुए और सजा पाए विदेशी नागरिकों को अपने-अपने समाज के अंदर ही अपनी सजा काटने का अवसर प्रदान कर पूरा किया जाना चाहिए;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद-1

परिभाषाएं

इस करार के प्रयोजनार्थ:

- (क) “निर्णय” से अभिप्राय सजा अधिरोपित करने संबंधी किसी न्यायालय अथवा अधिकरण का निर्णय अथवा आदेश है;
- (ख) “प्राप्तकर्ता राष्ट्र” से अभिप्राय ऐसे राष्ट्र से है, जिसमें कि सजायाफ्ता व्यक्ति को अपनी सजा काटने के उद्देश्य से अंतरित किया जा सकता है या किया गया है।

- (ग) “अंतरणकर्ता राष्ट्र” से अभिप्राय उस राष्ट्र से है जहां कि सजा अधिरोपित किए गए किसी व्यक्ति को अंतरित किया जा सकता है या किया गया है।
- (घ) “सजा” से अभिप्राय किसी भी प्रकार की सजा या उपाय से है, जिसमें किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा अपने आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किसी निश्चित कालावधि के लिए या जीवन भर के लिए स्वतंत्रता का हनन करना है या कैद करना है;
- (ङ.) “सजायाफ्ता व्यक्ति” से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी आपराधिक न्यायालय सहित संविदाकारी राष्ट्रों में तत्समय उनके कानून के तहत स्थापित न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के तहत कैद की सजा काट रहा है।

### अनुच्छेद-2

#### सामान्य सिद्धांत

1. किसी संविदाकारी राष्ट्र के भू-क्षेत्र में सजायाफ्ता किसी व्यक्ति को इस करार के उपबंधों के अनुसार उस पर अधिरोपित किए गए सजा काटने अथवा सजा की शेष अवधि काटने के लिए दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के भू-क्षेत्रों में अंतरित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए वह अंतरणकर्ता राष्ट्र या प्राप्तकर्ता राष्ट्र को इस करार के अंतर्गत अंतरित किए जाने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. अंतरण का अनुरोध किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति द्वारा जो संविदाकारी राष्ट्र का नागरिक हो, या संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविदाकारी राष्ट्र की सरकार द्वारा विहित तरीके से आवेदन करके किया जा सकता है।

### अनुच्छेद-3

#### केन्द्रीय प्राधिकरण

1. संविदाकारी राष्ट्रों के लिए इस करार से संबंधित निर्णय लेने और इसके कार्यान्वयन के प्रभारी प्राधिकरण इस प्रकार हैं:-
  - भारत गणराज्य के लिए: गृह मंत्रालय
  - बोस्निया एवं हर्जगोविना के लिए: बोस्निया एवं हर्जगोविना का न्याय मंत्रालय
2. यदि दोनों में से कोई भी संविदाकारी राष्ट्र अपने सक्षम प्राधिकारी में कोई परिवर्तन करता है तो वह सरकारी माध्यमों से इसे दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को अधिसूचित करेगा।

### अनुच्छेद-4

#### अंतरण की शर्तें

1. इस करार के अंतरण किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर अंतरित किया जा सकता है:
  - (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता राष्ट्र का राष्ट्रिक हो;
  - (ख) सजायाफ्ता व्यक्ति को मृत्यु दंड न दिया गया हो;
  - (ग) अंतिम रूप से निर्णय सुना दिया गया हो;
  - (घ) सजायाफ्ता व्यक्ति के विरुद्ध अंतरणकर्ता राष्ट्र में कोई जांच, मुकदमा या कोई अन्य कार्यवाही लंबित न हो;
  - (ङ.) अंतरण का अनुरोध प्राप्त होने के समय, सजायाफ्ता व्यक्ति की कम से कम छह माह की सजा शेष हो या वह उम्र कैद की सजा काट रहा हो;
  - (च) अंतरणकर्ता राष्ट्र में जिस कृत्य अथवा चूक के लिए सजा दी गई हो, प्राप्तकर्ता राष्ट्र में वह अपराध के रूप में दंडनीय हो या यदि उसके भू-क्षेत्र में घटित होती तो उसे एक अपराध माना जाता;
  - (छ) सजायाफ्ता व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए सजा न दी गई हो;

- (ज) प्राप्तकर्ता राष्ट्र में सजायाफ्ता व्यक्ति की अभिरक्षा का अंतरण, अंतरणकर्ता राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा अन्य किसी आवश्यक हित के प्रतिकूल न हो;
- (झ) यदि सजायाफ्ता व्यक्ति द्वारा या संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अंतरण का अनुरोध किया गया हो या सजायाफ्ता व्यक्ति की उम्र अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों में से कोई संविदाकारी राष्ट्र अंतरण को आवश्यक समझता हो; और
- (ञ) अंतरणकर्ता तथा प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरण के लिए सहमत हो।

2. आपवादिक मामलों में, अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता राष्ट्र, सजायाफ्ता व्यक्ति द्वारा काटी जाने वाली सजा की शेष अवधि छह माह से कम हो तो भी अंतरण करने पर सहमत हो सकते हैं।

### अनुच्छेद-5

#### सूचना प्रस्तुत करने का दायित्व

1. यदि किसी सजायाफ्ता व्यक्ति ने इस करार के अंतर्गत अंतरण हेतु सजा अधिरोपित करने वाले राष्ट्र के समक्ष रुचि व्यक्त की हो, तो अंतरणकर्ता राष्ट्र, प्राप्तकर्ता राष्ट्र को निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज भेजेगा, जब तक कि प्राप्तकर्ता राष्ट्र या अंतरणकर्ता राष्ट्र दोनों में से किसी ने भी पहले ही यह निर्णय ले लिया हो कि वे अंतरण पर सहमत नहीं होंगे:

- (क) सजायाफ्ता व्यक्ति का नाम व राष्ट्रीयता तथा जन्म की तारीख व स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता राष्ट्र में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) तथ्यों का विवरण, जिन पर सजा आधारित थी;
- (घ) सजा प्रारम्भ होने की तारीख, अवधि एवं प्रकृति;
- (ङ.) निर्णय की सत्यापित प्रति या कानून के संबंध प्रावधान की प्रति, जिसके अन्तर्गत सजायाफ्ता व्यक्ति के विरुद्ध सजा पारित की गई थी;
- (च) सजायाफ्ता व्यक्ति की चिकित्सीय, सामाजिक अथवा कोई अन्य रिपोर्ट, जो उसके आवेदन के निपटान अथवा उसके कारावास के स्वरूप निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो;
- (छ) कोई अन्य सूचना, जिसे प्राप्तकर्ता राष्ट्र सभी मामलों में अपेक्षित समझता है, ताकि वह अंतरण की संभावना पर विचार कर सके तथा अपने कानून के अंतर्गत सजायाफ्ता व्यक्ति को अंतरण के पूरे परिणामों के बारे में सूचित कर सके;
- (ज) अंतरणकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुसार अंतरित किए जाने वाले सजायाफ्ता व्यक्ति अथवा उसकी ओर से कार्रवाई कराने के लिए अधिकृत व्यक्ति का अनुरोध; और
- (झ) ऐसा विवरण, जिसमें दर्शाया गया है कि कितनी सजा पहले ही पूरी की जा चुकी है, जिसमें विचारण पूर्व कैद, माफी अथवा सजा लागू करने से संबंध कोई अन्य तथ्य शामिल है।

2. इस करार के अन्तर्गत किसी अनुरोध पर निर्णय लेने में सहायता करने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता राष्ट्र, अंतरणकर्ता राष्ट्र को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज भेजेगा, जब तक कि प्राप्तकर्ता अथवा अंतरणकर्ता राष्ट्र ने पहले से ही यह निर्णय नहीं ले लिया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं होगा:

- (क) ऐसा विवरण अथवा दस्तावेज, जिसमें दर्शाया गया हो कि सजायाफ्ता व्यक्ति, प्राप्तकर्ता राष्ट्र का नागरिक हो;
- (ख) प्राप्तकर्ता राष्ट्र के संबंध कानून की प्रतिलिपि, जिसके अनुसार ऐसी गतिविधि अथवा चूक के लिए अंतरणकर्ता राष्ट्र में सजा सुनाई गई है, मानो कि ऐसी गतिविधियां अथवा चूक, प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अन्तर्गत एक अपराध है अथवा यदि उनके भू-भाग में ऐसा किया जाता तो उसे अपराध माना जाता;
- (ग) सजायाफ्ता व्यक्ति के अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता राष्ट्र में सजा की अवधि तथा प्रवर्तन के संबंध में किसी कानून अथवा विनियम से संबंधित विवरण जिसमें, यदि लागू हो, तो उसके अंतरण के संबंध में इस करार के अनुच्छेद-9 के पैराग्राफ-2 से संबंधित विवरण शामिल है;

- (घ) सजायाफ्ता व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता राष्ट्र की इच्छा तथा सजायाफ्ता व्यक्ति की सजा के शेष भाग को पूरा करने की शपथ; और
- (ङ.) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज, जिसे अंतरणकर्ता राष्ट्र आवश्यक समझता है।

### अनुच्छेद-6

#### अनुरोध और उत्तर

1. अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप से निर्धारित प्रपत्र, यदि कोई हो, में किया जाएगा तथा यह अनुरोध अनुरोधकर्ता राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा राजनयिक माध्यमों से अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र के केन्द्रीय प्राधिकरण को संबोधित किया जाएगा। उत्तर के बारे में उन्हीं माध्यमों से सूचित किया जाएगा।
2. अनुरोध प्राप्तकर्ता राष्ट्र अनुरोधकर्ता राष्ट्र को सीधे ही अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह अंतरण के अनुरोध से सहमत है अथवा नहीं।

### अनुच्छेद-7

#### सहमति तथा इसका सत्यापन

1. अंतरणकर्ता राष्ट्र यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद-4 के पैराग्राफ-1 (i) के अनुसार अपेक्षित सहमति देने वाला व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से ऐसा करेगा तथा उसे उसके परिणामों की पूरी जानकारी होगी। ऐसी सहमति देने की प्रक्रिया अंतरणकर्ता राष्ट्र के कानूनों द्वारा शासित होगी।
2. अंतरणकर्ता राष्ट्र प्राप्तकर्ता राष्ट्र को यह सत्यापित करने का अवसर प्रदान करेगा कि यह सहमति इस अनुच्छेद के पैराग्राफ-1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार दी गई है।

### अनुच्छेद-8

#### प्राप्तकर्ता राष्ट्र के लिए अंतरण का प्रभाव

1. प्राप्तकर्ता राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-9 में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अपने राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत यथापेक्षित न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश के माध्यम से सजा का प्रवर्तन जारी रखेगा।
2. इस करार के अनुच्छेद-11 के अध्याधीन सजा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून द्वारा शासित किया जाएगा तथा केवल वही राष्ट्र सभी उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम होगा।

### अनुच्छेद-9

#### सजा का निरन्तर प्रवर्तन

1. प्राप्तकर्ता राष्ट्र, अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा यथा निर्धारित सजा के विधिक स्वरूप तथा अवधि द्वारा बाध्य होगा।
2. तथापि, यदि यह सजा अपने स्वरूप अथवा अवधि अथवा दोनों की दृष्टि से प्राप्तकर्ता राष्ट्र के कानून के अनुरूप नहीं है अथवा यदि उसके कानून के अन्तर्गत ऐसा अपेक्षित हो, तो वह राष्ट्र न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा इस सजा को अपने कानून के अन्तर्गत निर्धारित दंड अथवा कार्रवाई के अनुरूप बना सकता है। इस दंड अथवा उपाय का स्वरूप तथा अवधि यथासंभव अंतरणकर्ता राष्ट्र के निर्णय द्वारा लागू सजा के अनुरूप होगा। तथापि, इससे अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा सुनाई गई सजा का स्वरूप अथवा अवधि संवर्धित नहीं होगी।

### अनुच्छेद-10

#### अंतरणकर्ता राष्ट्र के लिए सजा पूरा होने के प्रभाव

इस करार के अनुच्छेद 13 के पाराग्राफ-1(क) के अन्तर्गत जब प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरणकर्ता राष्ट्र को यह अधिसूचित करता है कि सजा पूरी कर ली गई है, तब यह अधिसूचना अंतरणकर्ता राष्ट्र में सजा पूरी होने के रूप में प्रभावी होगी।

**अनुच्छेद-11****निर्णय एवं क्षमा, राजक्षमा की समीक्षा अथवा सजा कम करना**

1. अंतरणकर्ता राष्ट्र अकेले ही निर्णय की समीक्षा के लिए किसी आवेदन पर निर्णय लेगा।
2. कोई भी संविदाकारी राष्ट्र अपने संविधान अथवा दूसरे कानून के अनुरूप सजा को क्षमा, राजक्षमा अथवा इसे कम कर सकता है।

**अनुच्छेद-12****सजा के प्रवर्तन की समाप्ति**

1. प्राप्तकर्ता राष्ट्र को जैसे ही अंतरणकर्ता राष्ट्र द्वारा लिए गए ऐसे किसी निर्णय अथवा उपाय की सूचना मिलती है, जिसके परिणामस्वरूप सजा को लागू नहीं किया जा सकेगा तो प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजा के प्रवर्तन को रद्द कर देगा।

**अनुच्छेद-13****सजा लागू किए जाने संबंधी सूचना**

- (1) प्राप्तकर्ता राष्ट्र अंतरणकर्ता राष्ट्र को अधिसूचित करेगा:—
  - (क) जब सजा का प्रवर्तन पूरा हो जाए; अथवा
  - (ख) यदि सजा पूरी होने से पूर्व ही सजायाफ्ता व्यक्ति कैद से भाग जाता है तो ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजायाफ्ता व्यक्ति की गिरफ्तारी के भरसक प्रयास करेगा ताकि वह अपनी शेष सजा काट सके और यह कि कैदी के भाग जाने से संबंधित प्राप्तकर्ता राष्ट्र के प्रासंगिक कानून के तहत किसी अपराध के लिए कैदी पर मुकदमा चलाया जा सके।
- (2) यदि अंतरण करने वाले राष्ट्र के लिए अपेक्षित हो तो प्राप्तकर्ता राष्ट्र सजा लागू करने के लिए संबंध में विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**अनुच्छेद-14****पारगमन**

यदि संविदाकारी राष्ट्र, सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे राष्ट्र के साथ किसी प्रकार की व्यवस्था करता है तो दूसरा संविदाकारी राष्ट्र किसी भी सजायाफ्ता व्यक्ति जो उसके अपने देश के नागरिकों में से एक है, के पारगमन की अनुमति से इनकार करने के अपवाद को छोड़कर इस प्रकार की व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने भू-क्षेत्र के जरिए अंतरित किए जाने वाले सजायाफ्ता व्यक्तियों के पारगमन को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करेगा।

**अनुच्छेद-15****लागत**

इस करार को लागू किए जाने पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन, अंतरणकर्ता राष्ट्र के भू-क्षेत्र विशेष में हुए व्यय को छोड़कर, प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा किया जाएगा। तथापि, प्राप्तकर्ता राष्ट्र, यदि उनके घरेलू कानून/नियमों द्वारा अनुमत्य है तो सजायाफ्ता व्यक्ति अथवा अन्य स्रोत से अंतरण पर आने वाली पूरी अथवा आंशिक लागत को पूरा करने की मांग करेगा।

**अनुच्छेद-16****भाषा**

अनुरोध तथा समर्थन दस्तावेजों के साथ अनुरोधकर्ता राष्ट्र की भाषा अथवा उसकी राजभाषाओं में से किसी एक भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया जाएगा।

**अनुच्छेद-17****प्रवर्तन का क्षेत्र**

यह करार इस करार के लागू होने के पूर्व अथवा बाद में दी गई सजा के प्रवर्तन पर लागू होगा।

**अनुच्छेद-18****संशोधन**

संविदाकारी राष्ट्रों के बीच हुई सहमति से इस करार में किया गया किसी प्रकार का संशोधन अथवा आशोधन राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान द्वारा पुष्टि के बाद प्रभावी होगा।

**अनुच्छेद-19****अंतिम उपबंध**

(1) यह करार अनुसमर्थन किए जाने के अध्यक्षीन होगा और यह उस तारीख को लागू होगा जिस तारीख को अनुसमर्थन संबंधी दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

(2) यह करार उस तारीख से छह महीनों तक प्रभावी बना रहेगा जिस तारीख को दोनों में से कोई भी संविदाकारी राष्ट्र, दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को इस करार को रद्द करने की लिखित सूचना दे देता है।

(3) समाप्ति के बावजूद, यह करार उन सजायाफ्ता व्यक्तियों की सजा के संबंध में लागू होगा, जिन्हें इस करार के तहत इस प्रकार की समाप्ति के प्रभावी होने की तारीख से पूर्व अंतरित किया गया है।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपने-अपने प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सारायेवो में 13 दिसम्बर, 2012 के ..... दिन हिन्दी, अंग्रेजी और बोस्निया एवं हर्जोगोविना की राजभाषाओं (बोस्नियन, क्रोएशियाई और सर्बियाई) के दो-दो मूल पाठों में संपन्न; सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की ओर से

ह.

(गौरी शंकर गुप्ता)

भारत के राजदूत

बोस्निया एवं हर्जोगोविना की ओर से

ह.

(बरीसा कोलक)

न्याय मंत्री

[फा. सं. V-17011/25/2008-पी.आर.]

दिलीप कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(CS DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th July, 2017

**G.S.R. 950(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to Bosnia & Herzegovina. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of the Republic of India and Bosnia and Herzegovina on 13.12.2012 is given below. The Agreement was ratified by the Government of India on 14.2.2013 and by Bosnia & Herzegovina on 10.12.2015. The exchange of Instruments of Ratification was done on 21.7.2017.

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON THE  
TRANSFER OF SENTENCED PERSONS**

The Republic of India and Bosnia and Herzegovina hereinafter referred to as the Contracting States;

**Desiring** to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

**Considering** that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences in their own society;

**Have agreed** as follows:

**Article 1****Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- (a) "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
- (b) "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.
- (d) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (e) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;

**Article 2****General Principles**

(1): A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence or remainder of the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.

(2): Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the Government of that Contracting State.

**Article 3****Central Authorities**

(1) Authorities in charge for decision making and the implementation of this Agreement for the Contracting States are:

- For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
- For the Bosnia and Herzegovina: Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina

(2) In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other State of the same through official channels.

#### **Article 4**

##### **Conditions for Transfer**

(1): A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the death penalty has not been imposed on the sentenced person;
- (c) the judgment is final;
- (d) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;
- (e) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
- (f) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (g) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (h) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other interest of the transferring State;
- (i) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (j) the transferring and receiving States agree to the transfer.

(2) In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

#### **Article 5**

##### **Obligation to furnish information**

(1) If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
- (b) his address, if any, in the receiving State;
- (c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;

- (h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
- (i) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

(2) For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions, on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

## **Article 6**

### **Request and replies**

(1) Requests for transfer shall be made in writing in the prescribed proforma, if any, and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.

(2) The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

## **Article 7**

### **Consent and its verification**

(1) The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.

(2) The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

## **Article 8**

### **Effect of transfer for the receiving State**

(1) The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.

(2) Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

**Article 9****Continued enforcement of sentence**

(1) The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.

(2) If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

**Article 10****Effect of completion of sentence for the transferring State**

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

**Article 11****Review of Judgement and Pardon, amnesty or commutation**

(1) The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.

(2) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

**Article 12****Termination of enforcement of sentence**

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

**Article 13****Information on enforcement of sentence**

(1) The receiving State shall notify the transferring State:

(a) when the enforcement of the sentence has been completed; or

(b) if the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases the receiving State shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence and that the prisoner be prosecuted for committing an offence under the relevant law of the receiving State on escape of prisoner.

(2) The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

**Article 14****Transit**

If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

**Article 15****Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, if permitted by their domestic law/rules, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

**Article 16****Language**

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language or one of the official languages of the requesting State.

**Article 17****Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

**Article 18****Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed by the Contracting States shall come into effect when confirmed by an Exchange of Diplomatic Notes.

**Article 19****Final Provisions**

(1) This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of ratification are exchanged.

(2) The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.

(3) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective authorities, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Sarejevo on the 13<sup>th</sup> day of December 2012, in Hindi, English and official languages of Bosnia and Herzegovina (Bosnian, Croatian and Serbian), all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

**For the Republic of India**

**For Bosnia and Herzegovina**

**Sd/-**

**(GAURI SHANKAR GUPTA)**

**Ambassador of India**

**Sd/-**

**(BARISA COLAK)**

**Minister of Justice**

[F. No. V-17011/25/2008-PR]

DILIP KUMAR, Jt. Secy.